जयपुर में 15 अगस्त को आयोजित होने वाली देश की पहली बाल निगम सभा के पोस्टर का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मंगलवार को विमोचन किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की।

देश की पहली बाल निगम सभा 15 अगस्त को जयपुर में होगी

मुख्यमंत्री भजनलाल ने बच्चों के बीच बाल निगम सभा के पोस्टर का विमोचन किया

- **यह कार्यक्रम नगर निगम हैरिटेज, फ्यूचर सोसायटी तथा डिजिटल बाल मेला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगा।**
- **बाल निगम सभा में हैरिटेज निगम के चयनित बच्चे बाल पार्षद बनेंगे। वे निगम की बाल सभा में शहर की स्वच्छता से जुड़े मुद्दे उठायेंगे।**

जयपुर, 1 जुलाई। देश की पहली बाल विधानसभा का कीर्तिमान रचने के बाद अब राजस्थान पहली बाल निगम सभा आयोजित करने जा रहा है। यह सभा 15 अगस्त को नगर निगम हेरिटेज, फ्यूचर सोसायटी और डिजिटल बाल मेला के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित होगी। इस सभा के पोस्टर का विमोचन मंगलवार शाम मुख्यमंत्री निवास पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बच्चों के बीच किया। इस मौके पर उन्होंने बच्चों ने बातचीत भी की।

पोस्टर विमोचन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बच्चे स्वच्छ भारत के सच्चे बालदूत हैं। "कौन बनेगा बाल पार्षद" राजस्थान में एक बेहतरीन नवाचार है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्वच्छ भारत का सपना यह अभियान प्रदेश के सभी नगर निगमों में पूरा करेगा। इस आयोजन के लिए उन्होंने डिजिटल बाल मेला, फ्यूचर सोसाइटी और नगर निगम हेरिटेज को शुभकामनाएं दी हैं।

डिजिटल बाल मेला की जान्हवी शर्मा ने बताया कि इस अभियान के तहत होने वाली निगम की बाल सभा में हेरिटेज निगम के चयनित बच्चे बाल पार्षद बनेंगे और निगम की बाल सभा में शहर की स्वच्छता से जुडे मुद्दे उठाएंगे। यह आयोजन बच्चों की भागीदारी के माध्यम से स्वच्छ भारत मिशन को नई दिशा देने का एक महत्वपूर्ण प्रयास है।

गौरतलब है कि कौन बनेगा बाल पार्षद अभियान पिछले वर्ष 26 नवंबर को लॉन्च किया गया था। अभियान के तहत, हेरिटेज निगम के वॉर्डों के स्कूल, पार्क और ऐतिहासिक स्मारकों पर बच्चों की ओर से विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों ने पोस्टर, स्लोगन और सफाई गतिविधियों के माध्यम से आम जनता को ठोस कचरा प्रबंधन, प्लास्टिक के दुष्प्रभाव और गीले-सूखे कचरे के पृथक्करण के महत्व के बारे में जानकारी दी। अब हजारों प्रतिभागियों में से बच्चों का चयन कर, उन्हें बाल पार्षद बनाया जाएगा और उसके बाद सभा का आयोजन होगा।

जयपुर सैशन कोर्ट को "बम" से उड़ाने का ईमेल मिला

न्यायालय परिसर को तत्काल खाली कराके ली गई तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

- **परिसर की तलाशी में बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड व सुरक्षा एजेंसियों ने तत्परता से भाग लिया। न्यायालय भवन को सुरक्षित घोषित करने के बाद अदालत का कार्य दोबारा चालू हुआ।**
- **पुलिस की साइबर शाखा ई-मेल स्रोत की जानकारी कर रही है।**

-कार्यालय संवाददाता-

जयपुर, 1 जुलाई। राजधानी जयपुर में मंगलवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब सत्र न्यायालय (सेशन कोर्ट) को बम से उडाने की धमकी भरा ई-मेल मिला। इससे पूरे न्यायालय परिसर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार, यह धमकी न्यायालय के आधिकारिक ई-मेल पर भेजी गई थी। मेल की जानकारी मिलते ही न्यायालय प्रशासन ने तुरंत पुलिस और जिला प्रशासन को सूचित किया। इसके बाद बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के दल मौके पर पहुंचे और न्यायालय परिसर को तत्काल खाली करा कर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया। पूरा भवन छानने के बाद किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर के अलग-अलग हिस्सों में गहन जांच की। तलाशी अभियान के पूरा होने तक किसी तरह की संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर न्यायालय भवन को सुरक्षित घोषित किया गया। इसके बाद कार्य दोबारा शुरू हो गया। उधर साइबर शाखा ई-मेल के स्रोत की जांच में जुटी है।

बनीपार्क थानाधिकारी बृजमोहन कविया ने बताया कि मंगलवार दोपहर में यह ई-मेल प्राप्त हुआ था। सूचना मिलते ही पुलिस नियंत्रण कक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया गया। बाद में तत्परता से पूरे परिसर को खाली करवाकर तलाशी अभियान चलाया गया।

बम निरोधक दस्ते और डॉग स्क्वॉड की मदद से कोर्ट परिसर में सघन तलाशी अभियान चलाया गया। इसके अलावा मौके पर सिविल डिफेंस की टीम भी तैनात की गई। डॉग स्क्वॉड और बम निरोधक दस्ते ने कोर्ट परिसर को खाली करवाकर चप्पे-चप्पे की तलाशी ली। तलाशी में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिलने पर पुलिस और प्रशासन ने राहत की सांस ली। वहीं, मेल के बारे में साइबर टीमें काम कर रही हैं।

गौरतलब है कि 30 मई को जयपुर में फैमिली कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी। राजधानी जयपुर में इससे पहले भी कई बार सरकारी महकमों को बम से उड़ाने की धमकी देने के मामले सामने आए थे। एसएमएस स्टेडियम को बम से उड़ाने की कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। मेट्रो स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी भरे मेल आए थे। बाद में जब जांच हुई तो ये अफवाहें निकली थीं।

भारत व पाक ने कैदियों की लिस्ट का आदान प्रदान किया

- **दोनों देशों के बीच 2008 में हुए एक समझौते के तहत हर साल जनवरी व जुलाई में कैदियों को सूची साझा की जाती है।**
- **भारत ने 382 पाकिस्तानी कैदियों, 981 मछुआरों के नाम दिए और पाकिस्तान ने 53 भारतीयों व 193 मछुआरों के नामों की लिस्ट दी है।**

नयी दिल्ली, 01 जुलाई। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत तथा पाकिस्तान ने अपने-अपने देशों में हिरासत में रखे गये आम नागरिकों तथा मछुआरों की रिहाई के वास्ते सूची का आदान प्रदान किया है। भारत पाकिस्तान के बीच 2008 में हुए एक समझौते के तहत हर साल जनवरी और जुलाई में ऐसे कैदियों की सूचियों का आदान-प्रदान किया जाता है।

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के अनुसार भारत ने अपनी हिरासत में रखे गये 382 पाकिस्तानी कैदियों और 81 मछुआरों के नाम पाकिसतान को दिए हैं जबकि पाकिस्तान ने अपनी हिरासत में रखे 53 भारतीयों और 193 मछुआरों के नामों की सूची भारत को सौंपी है।

प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने पाकिस्तान की हिरासत में मौजूद अपने कैदियों, मछुआरों और उनकी नावों तथा लापता भारतीय रक्षा कर्मियों की शीघ्र रिहाई तथा स्वदेश वापसी का आ ान किया है।

उन्होंने पाकिस्तान से उन 159 भारतीय मछुआरों और नागरिक कैदियों की रिहाई में तेजी लाने को भी कहा है, जिन्होंने अपनी सजा पूरी कर ली है। इसके अलावा 26 ऐसे कैदी हैं जिन्हें भारतीय नागरिक माना जाता है इसलिए सरकार ने इन कैदियों और मछुआरों को तत्काल कानूनी सुविधा उपलबध कराने को कहा है।

भारत ने यह भी कहा है कि उन सभी भारतीय कैदियों और मछुआरों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जानी चाहिए जिनकी रिहाई लंबित है।

रेल मंत्री ..

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

अनुकूल इंटरफेस के साथ व्यापक, ऑल-इन-वन एप्लिकेशन है जिसको एंड्रॉइड प्ले स्टोर और आईओएस एप स्टोर पर डाउनलोड किया जा सकता है। यह एप अनारक्षित एवं प्लेटफार्म टिकट पर तीन प्रतिशत छूट, लाइव ट्रेन ट्रैकिंग, शिकायत निवारण, ई-कैटरिंग, पोर्टर बुकिंग और लास्ट माइल टैक्सी जैसी सभी यात्री सेवाओं को एकीकृत करता है। केंद्रीय मंत्री ने एप जारी करते हुए कहा कि रेलवन में सिंगल साइन-ऑन की सुविधा है, जिसमें एम-पिन या बायोमेट्रिक के जरिए लॉगिन किया जा सकता है। यह मौजूदा रेलकनेक्ट और यूटीएस क्रेडेंशियल को भी सपोर्ट करता है। रेलवन स्पेस सेविंग है क्योंकि इसके कारण उपयोगकर्ताओं को अलग-अलग सेवाओं के लिए अलग-अलग एप रखने की जरूरत नहीं पड़ती।

ट्रंप एक समय के घनिष्ठ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

उनकी आलोचना होने लगी थी। अपनी तयशुदा अवधि के बाद मस्क ने डीओजीई को छोड़ दिया और ट्रंप की संघीय खर्च योजनाओं की आलोचना शुरू कर दी। इसके जवाब में ट्रंप ने मस्क पर आर्थिक चोट की। उन्होंने अमेरिका में इलेक्ट्रिक वाहनों पर दी जाने वाली सब्सिडी कम कर दी। यह सब्सिडी मस्क की कंपनी टेस्ला को मिलती थी, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बनाती है। ट्रंप अब कहते हैं कि मस्क ने सरकारी सब्सिडी का भरपूर लाभ उठाया।

उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट कर कहा कि एलन मस्क इस सब्सिडी के सबसे बड़े लाभार्थी थे, और इसके बिना उन्हें "अपनी दुकान बंद कर दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ सकता था।" व्यंग्यात्मक अंदाज़ में उन्होंने कहा कि मस्क अब अंतरिक्ष यान भेजने या अपनी विशाल योजनाओं का मज़ा नहीं ले पाएंगे। हालांकि मस्क अमेरिका के प्राकृतिक नागरिक हैं, लेकिन उन्होंने ट्रंप को फिर से नाराज़ कर दिया जब उन्होंने मिड-टर्म चुनावों में एक ऐसे उम्मीदवार का समर्थन किया जिसे ट्रंप हराना चाहते थे। अब ट्रंप अपने प्रवासी विरोधी अभियान को और तेज़ी से चला रहे हैं।

विडंबना देखिए, ट्रंप ने एलन मस्क को देश से बाहर निकालने की बात उस समय कही जब वे फ्लोरिडा में एक बदनाम डिपोर्टेशन कैंप - एलिगेटर अलकाट्राज़ - का उद्घाटन करने जा रहे थे। अगर ट्रंप वाकई मस्क को अमेरिका से निकाल देते हैं, तो यह अमेरिकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंतिम टिप्पणी होगी।

'भगदड़ में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

कि इस भगदड़ में 11 लोगों की मौत हो गई थी। केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण का कहना है कि आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली। आरसीबी की पहली आईपीएल खिताबी जीत के बाद टीम द्वारा विधानसौधा से विजय परेड और स्टेडियम में प्रशंसकों के साथ जश्न के कार्यक्रम की घोषणा के बाद, स्टेडियम के पास एमजी रोड और कुब्बोन रोड इलाकों में लगभग ढ ाई लाख प्रशंसक उमड़ पड़े थे । कैट ने कहा, इसलिए प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि लगभग तीन से पांच लाख लोगों के एकत्र होने के लिए आरसीबी जिम्मेदार है। आरसीबी ने पुलिस से उचित अनुमति या सहमति नहीं ली। कैट ने अपने अवलोकन में कहा, अचानक उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया, जिसके परिणामस्वरूप लोग एकत्र हो गए। आरसीबी ने चार जून की सुबह की परेड और प्रशंसकों के कार्यक्रम के बारे में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था और न्यायाधिकरण ने पाया कि पुलिस विभाग के पास इतने कम समय में इतनी बडी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त समय नहीं था।

तमिलनाडु में पुलिस हिरासत में मौत की जांच सीबीआई करेगी

राज्य के मुख्यमंत्री स्टालिन ने यह बड़ा फैसला किया

- **ज्ञातव्य है कि शिवगंगा जिले में पुलिस ने पूछताछ के लिए 29 वर्षीय युवक अजीत कुमार को हिरासत में लिया था, जिसकी मौत हो गई। इस पर राज्य में भारी आक्रोश देखा गया, विपक्षी दलों व आम जनता ने भारी विरोध प्रदर्शन किया।**

चेन्नइ, 01 जुलाई। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में पुलिस हिरासत में हुई युवक की संदिग्ध मौत ने पूरे राज्य में हलचल मचा दी है। इस मामले में मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन ने बड़ा कदम उठाते हुए इसकी जांच सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया है। 29 वर्षीय अजीत कुमार की मौत को लेकर विपक्ष से लेकर आम जनता तक में भारी आक्रोश है।

मिली जानकारी के मुताबिक, अजीत कुमार को पूछताछ के लिए तिरुपुवनम पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसी दौरान कथित रूप से पुलिस की मारपीट के चलते उसकी मौत हो गई। मौत की खबर सामने आते ही, स्थानीय लोगों और अजीत कुमार के परिवार ने न्याय की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने बयान जारी कर कहा कि अजीत कुमार की मौत बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। उन्होंने कहा कि यह घटना पुलिस द्वारा की गई हिंसा का नतीजा है, जो किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं की जा सकती। स्टालिन ने कहा कि वह शुरू से ही पुलिस कर्मियों को मानवीय व्यवहार अपनाने की सीख देते रहे हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस विभाग ने पहले ही छह पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया था। अब इनमें से पांच पुलिसकर्मियों को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं, जिले के एसपी को अनिवार्य प्रतीक्षा पर भेज दिया गया है और एक डीएसपी को भी सस्पेंड कर दिया गया है।

मुख्यमंत्री स्टालिन ने अजीत कुमार के परिजनों से बातचीत कर उन्हें न्याय दिलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जांच निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से की जाएगी, ताकि पीड़ित परिवार को न्याय मिल सके और दोषियों को सजा दिलाई जा सके।

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने पहले इस मामले में सीबी-सीआईडी जांच की अनुमति दी थी। लेकिन, पांच पुलिसकर्मियों पर सीधे आरोप लगने और जनता में भरोसा कायम रखने के लिए मुख्यमंत्री ने अब जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला लिया है।

मुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग को सख्त संदेश देते हुए कहा कि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पुलिस को जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहिए और उनकी समस्याओं का समाधान संवेदनशीलता के साथ करना चाहिए। राज्य सरकार इस मामले में सीबीआई को पूरा सहयोग देगी।

तमिलनाडु में ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

सत्तूर टाउन पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। पुलिस ने फैक्ट्री के फोरमैन को गिरफ्तार कर लिया है। इस बीच, मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने शोक संतप्त लोगों के प्रति अपनी संवेदना जतायी है। उन्होंने मृतकों के परिवारों को चार-चार लाख रुपये तथा घायलों को एक-एक लाख रुपये की सहायता राशि देने की भी घोषणा की।

नया स्वदेशी युद्धपोत उदयगिरी नौ सेना में शामिल

यह पोत तय समय से पहले ही नौसेना को सौंप दिया गया है

- **इस श्रेणी के कुल 7 युद्धपोत और बनाए जाएंगे जो अगले वर्ष के अंत तक नौसेना को सौंप दिए जाएंगे।**

नयी दिल्ली/ पणजी, 01 जुलाई। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएसएल) में निर्मित प्रोजेक्ट 17ए का दूसरा स्टेल्थ फ्रिगेट 'उदयगिरि' मंगलवार को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया। यह प्रोजेक्ट 17ए के तहत शिवालिक श्रेणी का दूसरा जहाज है। इस श्रेणी के कुल सात स्टेल्थ युद्ध पोत (फ्रिगेट्स) बनाए जाने हैं और इन्हें अगले वर्ष के अंत तक नौसेना को सौंपा जा सकता है।

रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक विज्ञिप्त में बताया कि उदयगिरि को तय तारीख से पहले 37 महीने के रिकॉर्ड समय में भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया है। यह फ्रिगेट बहुत-से मिशनों के लिए कार्य करने में सक्षम है। इसमें रडार या अन्य टोही उपकरणों से बच कर कार्रवाई करने की विशेषताएं बढ़ाई गई हैं। ये जहाज अत्याधुनिक हथियारों और सेंसरों से लैस हैं।

इन जहाजों पर भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो की अपनी अभूतपूर्व डिजाइन क्षमताओं की छाप है।

ये पोत पूर्ववर्ती पी-17 जहाजों की तुलना में 4.54 प्रतिशत अधिक बड़े हैं। इन जहाजों को पी-17 वर्ग की तुलना में अधिक आधुनिक और रडाररोधी विशेषताओं वाले उन्नत हथियारों और सेंसर से लैस किया गया है। इस जहाज को सतह से सतह पर मार करने वाली सुपरसोनिक मिसाइल प्रणाली, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली, 76 मिमी गन तथा तीव्र गति से गोलाबारी करने वाली 30 मिमी और 12.7 मिमी की हथियार प्रणालियों से लैस किया गया है।

22 राज्यों ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

और पश्चिम बंगाल में भी जल्द ही प्रदेश अध्यक्षों के चुनाव होंगे। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ विधायक हेमंत खंडेलवाल एकमात्र नामांकन करने वाले उम्मीदवार थे, जिससे उनका चुनाव महज औपचारिकता बन गया है। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने बताया कि केन्द्रीय नेतृत्व ने ऐसे नेताओं को चुना है जो किसी गुट के नेता नहीं माने जाते और जिनकी स्वीकार्यता व्यापक है। पार्टी के संविधान के अनुसार, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 37 संगठनात्मक राज्यों में से कम से कम 19 में प्रदेश अध्यक्षों का चुनाव जरूरी है।

'वन बिग ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

चेतावनी दी यदि यह पागलपन वाला खर्च विधेयक पारित हो जाता है, तो अगले दिन अमेरिका पार्टी का गठन किया जाएगा। हमारे देश को डेमोक्रेट-रिपब्लिकन यूनिपार्टी के विकल्प की आवश्यकता है ताकि लोगों के पास वास्तव में एक आवाज हो।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा राष्ट्रदूत प्रेस, जी1/63 इंडस्ट्रीयल एरिया फेस प्रथम, जालौर, (राज.) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. RAJHIN/2006/17286 जयपुर कार्यालय: सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34, फैक्स : 0141-2373513, कोटा कार्यालय : पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, बीकानेर कार्यालय : कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, उदयपुर कार्यालय: आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, अजमेर कार्यालय: राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर। फोन: 2627612, फैक्स:0145-2624665 जालोर कार्यालय :- जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन226422,226423, फैक्स: 02973-226424 हिण्डौनसिटी कार्यालय :- जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 चूरू कार्यालय : एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908